ANUPRAJNA
National E-Journal (An Open Acess Multidisciplinary Multilingual
Peer Reviewed and Referred Journal

विश्व रंगमंच पर प्रधानमंत्री शास्त्रीजी

भरत परमार
एज्युकेशन कॉलेज अमरेली गुजरात

Paper Received on:
06/11/2021

Paper Accepted on:
01/12/2021

प्रधानमंत्री बनने के बाद ही शास्त्रीजी ने वैदेशिक सम्बन्धी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार का काम शुरू कर दिया। सरदार स्वर्णसिंह पहली बार पूरे समय के लिए पर राष्ट्रमंत्री बने। अफगानिस्तान, बर्मा, लंका जैसे पड़ोसियों से अधिक मधुर सम्बन्धों की स्थापना के लिए कूटनीतिक कार्रवाई की गई। परन्तु एक खतरनाक और असामयिक दिल के दौरे के कारण, जो उनके जीवन में दूसरा था, शास्त्रीजी की महत्वकांक्षी योजनाओं को धक्का लगा। दिल के इस दौरे ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया और प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के एक मास के भीतर ही उन्हें हिलने-डुलने लायक न छोड़ा। इस मजबूरी में वह प्रधानमंत्री के रूप में लंदन में ८ जुलाई, १९६४ को हुए राष्ट्रमंडलीय प्रधानमंत्री सम्मेलन में भाग न ले सकें और उन्हें अपनी प्रथम विदेश-यात्रा रद्द कर देनी पड़ी। लंदन सम्मेलन में वित्तमंत्री श्री टी.टी. कृष्णमचारी और इन्दिरा गाँधी ने उनका प्रतिनिधित्व किया। इस प्रकार लालबहादुर का विश्व रंगमंच पर शानदार प्रवेश अक्टूबर तक नहीं हो पाया, जब उन्होनें काहिरा में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होनें बड़ी प्रभावशाली भूमिका अदा की। भारत के राजनीतिक संदेशवाहक शास्त्रीजी की काहिरा-यात्रा की तैयारी के लिए और चीन से विवाद व कश्मीर-समस्या पर भारतीय दृष्टिकोण से उन सरकारों को अवगत कराने के लिए अफ्रीकी राजधानियों की और पहल से रवाना कर दिए गए थे।काहिरा सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए लाल बहादुर ने कहा ''शांति को दृढ़ करने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम बनाने का समय आ गया है।'' उन्होनें एक पांचसूत्री कार्यक्रम का सुझाव दिया : (१) आण्विक निरस्त्रीकरण (२) सीमा विवादों पर शांतिपूर्ण का समझौता (३) विदेशी दासता, आक्रमण, घुसपैठ या तोड़फोड़ और रंगभेद से मुक्ति (४) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आर्थिक विकास में तेजी और (५) संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा उसके शांति एवं विकास कार्यक्रमों में पूर्ण सहयोग।

इन व्यगताजनक संकेतों का कि चीन शीघ्र ही आण्विक विस्फोट करने वाला है जिक्र करते हुए शास्त्रीजी ने प्रस्ताव किया कि सम्मेलन चाहे तो आण्विक हथियारों के विकास के पथ से चीन को हटने को राजी करने के लिए

एक विशेष प्रतिनिधिमंडल भेजनें के प्रश्न पर भी विचार करें। उन्होंने दृढतापूर्वक कहा कि भारत आण्विक शक्ति का केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही उपयोग करने पर संकल्पबद्ध है यद्यपि भारत में ''विशुद्ध प्राविधिक और वैज्ञानिक अर्थो में'' आण्विक अस्त्रों के विकास की भी क्षमता है।

लालबहादुर की पंचसूत्री शांति योजना सबको जंची और सच पूछा जाए तो आन्तर्राष्ट्रीय शांति के प्रश्न पर स्वीकृत प्रस्ताव के अन्तिम रूप को उसने बहुत अंशों में प्रभावित किया। उनकी काहिरा यात्रा के बाद वहाँ एकत्र अफीकी एशियाई राजनीतिज्ञों की नजर में यह निश्चित हो गया कि शास्त्रीजी नेहरू के सुयोग्य उत्तराधिकारी तथा सहअस्तित्व और विश्वशांति के प्रबल समर्थक है।

लौटते हुए शास्त्रीजी कराची में रूके, जहाँ राष्ट्रपति अयूब ने हवाई अड्डे पर उनसे भेंट की। दोनों नेताओं के बीच डेढ़ घंटे तक मैत्रीपूर्ण बातचीत हुई। बाद में जारी की गई विज्ञप्ति में बताया गया कि दोनों नेताओं का दृढ़ मत है कि भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध को सुधारने की जरूरत है ताकि दोनों अच्छे पड़ोसी की तरह एक-दूसरे का हित करें।

दोनों नेता इस बात परस हमत थे कि ''दोनों देशों के बीच सद्भाव बढ़ाना और सम्मान तथा न्याय के आधार पर आपसी झगड़ो तथा पेचीदी समस्याओं को हल करना जरूरी है।'' राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत विचार-विनिमय के इस अवसर का स्वागत करते हुए कहा कि इन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, यह तय करने के लिए दोनों परस्पर सम्पर्क बनाए रखेंगे।

शास्त्रीजी ने स्वयं भी कराची वार्ता को ''एक शुभ आरम्भ'' कहा था।

महीना भी न बीत पाया था कि शास्त्री के मुकुट में सफलता का एक नग और जड़ गया। ३० अक्टूबर को भारत-लंका समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने से एक ऐसी पेचीदा समस्या हल हो गई जिसका समाधान लगभग १७ वर्षो से नहीं हो पा रहा था। इस समझोते से उस द्वीप में बसे ९,७०,००० नागरिकता विहीन भारतीयों का भविष्य निश्चित हुआ। यह लंका की प्रधानमंत्री श्रीमति श्रीमाओ भंडारनायके की एक सप्ताह की भारत यात्रा का सुपरिणाम था।

इस दस सूत्री समझौते में ३,००,००० भारतीय निवासियों को लंका की नागरिकता प्रदान करने और ५,२०,००० के भारत लौट आने की व्यवस्था थी। पूरी प्रक्रिया १५ वर्षो में पूरी होने को थी। बाकी बचे १,५०,००० लोगों की स्थिति पर बाद में विचार होना निश्चय हुआ। समझौते के अनुसार लंका छोड़कर भारत आने वाले भारतीयों को चालू मुद्रा विनिमय नियंत्रण नियमों के अधीन अपने साथ अपनी सब संपदा, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी आदि ले जाने की इजाजत थी।

२४ नवम्बर को लोकसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने फिर दोहराया कि भारत ने परमाणु बम न बनाने का निश्चय किया है और यह निश्चय केवल नैतिक आधार पर ही नहीं, किन्तु व्यावहारिक और वास्तविक बातों को विशेषकर ऐसे प्रयास का वर्तमान स्थिति में वित्तीय व्यवस्था पर कितना भयावह प्रभाव पड़ेगा, इस तथ्य को भी ध्यान में रखकर किया गया है। फिर भी उन्होनें स्वीकार किया कि संसद को इस नीति को बदल देने का पूरा अधिकार है और यह नीति अथवा कोई अन्य नीति सदा के लिए सही नहीं हो सकती। उन्होनें कहा कि देश कि सदा के लिए दृढ़ और लचकहीन रवैया व्यक्ति तो अपना सकते हैं लेकिन राष्ट्र ऐसा नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री के रूप में संसद में यह उनका दूसरा भाषण था जिसकी व्यापक रूप में सहायता से सराहना हुई थी।सदन से बाहर लाबी की राय यह थी कि अपनी बुनियादी नीति त्यागे बिना, शास्त्रीजी ने संसद और जनत में हो रही इस आलोचना का उचित उत्तर दे दिया है कि चीन के आण्विक बम द्वारा प्रस्तुत खतरे के मुकाबले में सरकार लचकहीन और हठी दृष्टिकोण अपना रही है।

दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में शास्त्रीजी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर तीन दिन के लिए लंदन की यात्रा की। अनिवार्यत: हेरल्ड विलसन से उनकी बातचीत का मुख्य विषय चीन के परमाणुबम का गैर-आण्विक राष्ट्रो पर असर था। शास्त्रीजी ने कहा कि बड़ी आण्विक शक्तियों की ओर से गारंटी मिलनी चाहिए कि चीन का आण्विक आक्रमण कुछ न बिगाड़ सकेगा। इस यात्रा में शास्त्रीजी ने ब्रिटिश उद्योग संघ के तत्वाधान में चोटी के ब्रिटिश व्यापारियों से भी भेंट की और उन्हें भारत में राजनीतिक स्थिरता तथा आर्थिक लाभ के अवसर तथा देश में निजी क्षेत्र को प्राप्त स्वतंत्रता तथा अनुकूलता का आश्वासन दिलाकर उन्हें भारत में पूँजी कर लगा इन सुविधाओं का लाभ उठाने का निमंत्रण भी दिया। उस समय ब्रिटिश उद्योगपतियों के मन में सबसे बड़ी परेशानी पेटेंट के प्रश्न पर थी। शास्त्रीजी ने उन्हें बताया कि निकट भविष्य में पेटेंट कानून में परिवर्तन का कोई इरादा नहीं है।

फरवरी १९६५ में चार विदेशी राजनयिकों का नई दिल्ली में स्वागत किया गया - फांस के प्रधानमंत्री जार्ज पांपिढू, बर्मा के राष्ट्रपति जनरल ने विन, फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉ. उरहो कलेवा केकोनेन और अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री डा. युसुफ। कच्छ सीमा पर पाकिस्तान द्वारा शुरू की गई लड़ाई से भी इन राजकीय यात्राओं में कोई बाधा नहीं पड़ी। कच्छ कांड जनवरी १९६५ के अन्त में आरम्भ हुआ, मार्च में जमकर गोलाबारी होने लगी और अप्रैल में उसने दो देशों की सेनाओं के बीच पूर्ण संग्राम का विस्फोटक रूप ग्रहण कर लिया।

ऐसे स्थल पर लड़ने की विवशता से जो सुरक्षा के लिए असुविधाजनक था, भारत को आरंभ में आक्रामकों के हाथ कुछ भूमि छोड़नी पड़ी। भारतीय सीमा पुलिस से कंजरकोट छीनने और सिब-कच्छ सीमा पर पूरी नियमित

सेना तैनात करने के बाद पाकिस्तान ने दो सरकारों के बीच शांति वार्ता का प्रस्ताव किया। प्रस्ताव स्वीकार करते हुए शास्त्रीजी ने लोकसभा के एक भाषण में जोर देकर कहा कि पहले पाकिस्तान कंजरकोट से हटे तभी कोई वार्ता हो सकेगी। भारत सरकार ने पाकिस्तान का यह दावा ठुकरा दिया कि कंजरकोट पाकिस्तान की सीमा में है। पाकिस्तान ने कंजरकोट से हटने से इन्कार किया और प्रस्ताव समाप्त हो गया। लड़ाई दूने वेग से २४ अप्रैल को फिर शुरू हो गई जब पाकिस्तान ने पहली बार टैंको और १०० पौंड वाली तोपों का प्रयाग करके तीन मोर्चो पर आक्रमण कर दिया आक्रमण को भारतीय सेना ने पीछे धकेल दिया जो इस बीच सीमा-पुलिस का स्थान ग्रहण कर चुकी थी। इस प्रकार पाकिस्तानी नेता शांति तथा समझौते की बात करते रहते थे जबकि उनकी सेना लड़ाई को उग्र बना रही थी। २८ अप्रैल को, लोकसभा के चिरस्मरणीय भाषण में लालबहादुर ने घोषणा की : ''यदि पाकिस्तान नासमझी और आक्रमणात्मक कार्रवाइयों को नहीं छोड़ता तो हमारी सेना देश की रक्षा करेगी, वह अपनी रणनीति तय करेगी और अपनी जनशक्ति तथा सामरिक सामना का उचित प्रयोग करेगी।''

इस गंभीर चेतावनी के बाद भारतीय सेना पंजाब सीमा तक आगे बढ गई। राज्य सभा ने ३ मई को ''भारत की पवित्र भूमि पर से पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को खदेड़ बाहर करने के'' भारतीय जनसंकल्प को दोहराया। इस बीच हेरल्ड विलसन ने युद्ध विराम प्रस्ताव द्वारा बीच बचाव किया और वस्तुत: युद्धविराम हो भी गया जिसे २५ मई को एक भारतीय गश्ती दल पर आक्रमण करके पाकिस्तान ने सहसा तोड़ दिया। इसीके बाद कच्छ सीमा के अन्य स्थानों पर और लड़ाई हुई। २७ जून को लंदन में, जहाँ राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्री सम्मेलन हो रहा था, शास्त्री और अयूब मिले तथा कच्छ सीमा पर युद्ध विराम प्रस्ताव के बारे में आगे बात हुई। लेकिन ३० जून से पहले भारत-पाक समझौते की औपचारिक घोषणा न हो सकी और युद्धविराम १ जुलाई से लागू हो गया।

अब जाकर शास्त्री को दम लेने की फर्सत मिली और उनकी विदेश यात्राओं का सिलसिला शुरू हुआ। अप्रैल में काठमाण्डू के लोगों ने लालबहादुर का बड़े प्रेम और मैत्रीभाव से स्वागत किया। उन्हें अपने देश में उनकी पहली यात्रा की याद आई जिससे वे सब बहुत प्रभावित हुए थे। मई में अपने विदेशमंत्री को साथ लेकर लालबहादुर आठ दिन की यात्रा पर सोवियत संघ गए। प्रत्येक दृष्टि से यह यात्रा बहुत ही उपयोगी रही। प्रधानमंत्री कोसीगिन और अन्य सोवियत नेताओं ने उनका बहुत मैत्रीपूर्ण स्वागत किया और तीन हजार शब्दों वाली संयुक्त विज्ञप्ति में यात्रा को ''रूस-भारत सम्बन्धों में मील का नया पत्थर'' बताकर घाषणा की गई कि ''सीमा और क्षेत्रीय झगड़े तय करने के लिए बल प्रयोग की इजाज़त नहीं होनी चाहिए।'' सब जान गए कि यह इशारा चीन और पाकिस्तान की ओर है। वस्तुत: तब चीन संवाद समिति ने एक समीक्षा में रूस पर चीन के विरूद्ध भारत से दोस्ती गांठने का

आरोप लगाया था। मास्को यात्रा का महत्व यह भी था कि इसी अवधि में लालबहादुर ने अपने तथा अपनी नीतियों के बारे में रूसी नेताओं की शुरू में जो सन्देह हुए थे उन्हें मिटा दिया।

अगले मास शास्त्री ने दे दो और देशों की यात्रा की। वह पांच दिन के लिए कनाड़ा गए और उसके बाद एक हफ्ते के लिए राष्ट्रपति नासिर से बात करने के लिए वह साढ़े तीन घंटे काहिरा में रूके। सच तो यह है कि घर की वापसी में अल्जीयर्स में अफोकी एशियाई सम्मेलन में भाग लेना भी उनके यात्रा कार्यक्रम में शामिल था किन्तु अल्जीयर्स सम्मेलन को एक राज्य क्रान्ति के कारण, जिसने बेनबेला सरकार को उखाड़ फका, रद्द कर देना पड़ा था।

ओटवा में, प्रधानमंत्री लेस्टर पियर्सन ने बड़े प्रेम से शास्त्रीजी का स्वागत किया। अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों की लम्बी सूची पर दोनों नेताओं ने कई बार विचार-विनिमय किया। शास्त्रीजी ने इस अवसर का उपयोग अपने मन में सबसे अधिक व्यग्रताजनक विषय यानी आण्विक शस्त्रास्त्रों के विस्तार तथा आण्विक आक्रमणों के विरूद्ध गैर आण्विक राष्ट्रों को आश्वासन दिए जाने के प्रश्न पर पियर्सन के विचार जानने के लिए किया। दोनों ने युद्ध के लिए आण्विक शस्त्रों के उपयोग की कटु आलोचना की। कई अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर दोनों के विचारो में एकरूपता थी।परन्तु कनाडा के नेताओं से बातचीत करने के बाद शास्त्रीजी यह दृढ़ धारणा बना कर घर लौटे कि पाकिस्तान से भारत का झगड़ा होने पर पश्चिमी राष्ट्र हंमेशा पाकिस्तान की ओर रहेंगे और ऐसे स्पष्ट मामलों पर भी जैसे कच्छ में पाकितस्तानी आक्रमण अथवा भारत के विरूद्ध पाकिस्तान द्वारा अमरीकी हथियारों का उपयोग यह देश मौन रहेंगे।

शास्त्रीजी १६ जून को लंदन पहुँचे। राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्री सम्मेलन में उन्होनें हेरल्ड विलसन के इन प्रस्ताव का समथन किया कि वियतनाम युद्ध से सम्बन्धित सरकारों से मिलने के लिए एक राष्ट्रमंडल शांति दल वहाँ भेजा जाए। लेकिन उनका सझाव था कि अभी तो प्रतिनिधिमंडल की कार्यपरिधि तय करने के लिए एक दल बना दिया जाए। सम्मेलन ने यह सुझाव मान लिया।

शास्त्रीजी ने इस शान्ति दल क लिए तीन निर्देशक सिद्धांत बताए :

(१) उत्तरी वीयतनाम पर अमरीकी बमवर्षा बंद हो और दोनों पक्ष लड़ाई रोक दें

(२) बाहरी सेनाएँ हटा ली जाएँ और शांतिपूर्वक नई व्यवस्था कायम करने के लिए वहाँ अफोकी-एशियाई सैन्यदल भेजा जाएँ तथा

(३) नीयतनाम की गुत्थी सुलझाने के लिए जेनेवा जैसा सम्मेलन बुलाया जाए।

सम्मेलन ने यह निर्देशक सिद्धांत स्वीकार कर लिए। यहाँ तक हुआ कि ''न्यूयार्क टाइम्स'' ने भारतीय प्रधानमंत्री के प्रस्तावों को व्यावहारिक तथा वांछनीय बता कर आग्रह किया कि अमरीकी राष्ट्पति को इन्हें मान लेना चाहिए राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्री सम्मेलन में शास्त्रीजी का एक और योगदान था। उनका आग्रह था कि राष्ट्रमंडल के विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को दी जानेवाली सहायता पर ब्याज की दरें और घटाई जाएँ तथा अदायगी की सुविधाएँ बढ़ाई जानी चाहिए।

१९६५ में भारतीय राष्ट्र का मनोबल निम्नतम स्तर पर था। १९६२ में फौजी दृष्टि से नीचा देखने के बाद हीनता की जो मनोवृत्ति पैदा हुई वह अब गहरी होकर अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर तीखी पराजय का रूप ग्रहण कर चुकी थी।

देश में आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी। भाव चढ़ रहे थे, कर बढ़ रहे थे। पस्तहिम्मती की इस दशा में देश के भीतर पृथकतावादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिल रहा था जबकि गुटसंघर्ष और विघटनकारी मनोवृत्ति दल के भीतर दराद बनकर सामने आ गई थी। अब लालबहादुर को विरोधी पक्ष के भरपूर आघात झेलने थे। उनका मत था कि पंच फसले की बात मानकर पाकिस्तान को अनुचित रियायत दी गई है। लालबहादुर ने संसद और काँग्रेस महासभा दोनों में, क्योंकि वहाँ भी उनकी कठोर आलोचना हुई, स्वाभाविक दृढ़ता से समझौते के पक्ष में सफाई दी। बाद में सितम्बर के अन्त में जब पाकिस्तानी सेना ७५ टैंकों सहित जम्मू सहित छमब क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार करके घुस आई तो लालबहादुर ने बिना एक क्षण हिचके वायु सेना को स्थल सेना की मदद का आदेश दिया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पर उन्होनें भारतीय सेना के तीन दस्तों को तीन दिशाओं से अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार कर पश्चिमी पंजाब में घुसा दिया ताकि छम्ब में पाकिस्तानी आक्रमण का जोर समाप्त हो जाए। अयूब खाँ नई दिल्ली की तीखी प्रतिक्रिया और सुनियोजित तीन चरण वाले अपने कश्मीर आक्रमण के पहले दाँव पर ही भारतीय सेना के सवाये जोरदार जवाबी हमले को देखकर चौंक से पड़े। भारत सरकार की प्रतिक्रिया पिछले १७ वर्षो से भारत द्वारा बरती गई आगे-पीछे वाली परंपरागत शांतिवादी नीति से एकदम विपरीत थी।

लालबहादुर ने लगाम छोड़ दी और भारतीय फौज उमड़कर बढ़ चली। अब उसे घुसपैठियों के आने-जाने के रास्ते बंद करने के लिए कश्मीर में युद्ध विराम रेखा को पार करने में या सीमा के उस पार के सामरिक महत्व के स्थलों पर कब्जा करने में संकोच न था। पश्चिमी पाकिस्तानी भूमि के बहुत भीतर स्थित पाकिस्तानी अड्डों पर जहाँ से कश्मीर तथा शेष देश पर हमले किए जाते थे, स्थल या वायु से हमला करने में अब कोई बाधा न रही। २२ दिन की लड़ाई स्थगित होने तक अयूब ने देख लिया कि भारतीय सेना लाहौर और स्यालकोट के पिछले अहाते में बैठी है और पाकिस्तानी फौज के बख्तरबंद टैंक लुज हो गए हैं, तथा वायु सेना की अच्छी मरम्मत की जा चुकी है।

भारतीय फौजों द्वारा की जाने वाली निर्मम चोटों से सामरिक महत्व वाले शहर सयालकोट की सुरक्षा में दराद पड़ गई थी और सिंघ सीमा पर घमासान युद्ध हो रहा था, तब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आग्रह पर युद्धविराम की घोषणा की गई।

पाकिस्तानी हमले की पूर्वसंध्या पर राष्ट्रपति अयूब ने भारतीयों को यह घृष्टतापूर्ण चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान के विरूद्ध युद्ध छेड़ने का सौदा कितना मँहगा पड़ेगा यह वे नहीं जानते। अब एक सप्ताह बाद वही अयूब संयुक्त राष्ट्रसंघ के महामंत्री की अपील के जवाब में ''शांतिपूर्ण युद्धविराम और सम्मानपूर्ण समझौते'' का आग्रह कर रहे थे।

अमेरीकी सरकार के एक प्रवक्ता ने राष्ट्रपति अयूब द्वारा प्रस्तावित भारत पाकिस्तान के झगड़े में अमेरीका के राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना से इन्कार कर दिया। नई दिल्ली में शास्त्री ने इसका जवाब अधिक सतर्कता से दिया। १६ नवम्बर को उन्होनें लोकसभा में कहा : ..खबरों के अनुसार, अन्य बातों के अलावा उन्होनें (अयूब ने) यह भी माना कि समझदारी का तकाजा है कि भारत और पाकिस्तान एक साथ शान्तिपूर्वक रहें। अगर इस नए विचार में ईमानदारी है तो मैं इसका बहुत स्वागत करूँगा, चाहे कितनी ही देर से यह क्यों न आया हो। लेकिन अगर पिछले अनुभव कुछ सिखाते हैं तो ये विचार दुनिया को धोखे में रखने के लिए प्रचार मात्र जान पड़ते हैं। पहले भी राष्ट्रपति अयूब ने शांति के गुणों की चर्चा की थी, और उसके बाद कच्छ में, फिर कश्मीर में, बिना किसी उत्तेजनात्मक कारण के भारत पर हमला कर दिया। भारत पाकिस्तान संघर्ष रोकने के लिए ऊ थां के प्रयासों के प्रति लाल बहादुर की प्रतिक्रिया अधिक स्पष्ट तथा दुविधारहित थी। वह तुरन्त बिना शर्त युद्ध रोकने को राजी हो गए यदि पाकिस्तान भी युद्ध विराम मान लें। उन्होनें इस प्रस्ताव को हूबहू स्वीकार करने में जो कठिनाई थी उसे भी स्पष्ट कर दिया। वह यह कि उस समय तक जम्मू कश्मीर में आए प्राय: दो हजार घुसपैठियों से निपटाने की समस्या और आगे घुसपैठ रोकने की सख्त जरूरत।

१७ सितम्बर को राष्ट्रपति अयूब के नए मित्र चेयरमेन माओत्सेतुंग ने उनकी मदद की। पेकिंग ने भारत को जोरदार शब्दों में चेतावनी दी और सिक्किम सीमा के पार चीन की भूमि पर भारत ने उनके अनुसार जो फौजी मशीनें यंत्र आदि लगा रखे हैं उन्हें तीन दिन के भीतर हटा लेने की माँग की । इस चेतावनी पर चीन को वाशिंगटन और मास्को से जवाबी चेतावनी मिली कि चीन भारत-पाकिस्तान उपमहाद्वीप में लगी आग से हाथ न सेकें।

पेकिंग के तीन दिन के अल्टीमेटम से लालबहादुर के कदम जरा भी नहीं डगमगाये। महान गंभीरता का प्रदर्शन करते हुए शास्त्रीजी ने संसद के सामने चीन के इस आरोप को झूठा बताया कि सिक्किम क्षेत्र में भारत की

ओर से कहीं भी सीमा-उल्लघंन हुआ है लेकिन शांति की सुरक्षा के लिए चीन के इस प्रस्ताव को मान गए कि दोनों देशों के प्रतिनिधि मिल कर इस आरोप की जाँच करे।

इसके बाद प्रधानमंत्रीने कहा, ''हमें आशा है कि चीन वर्तमान स्थिति का अनुचित लाभ उठा कर भारत पर हमला नहीं करेगा। उन्होनें सदन को आश्वासन दिया कि हम दृढसंकल्प होकर अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए अवश्य लडेंगे। चीन की शक्ति हमें अपनी मातृभूमि की अखंडता की रक्षा करने से नहीं रोक सकती।''

शास्त्रीजी ने आगे कहा, ''हमारी समझ में अल्टीमेटम की अवधि बढाने का उद्देश्य केवल यह है कि सुरक्षा परिषद में बहस का परिणाम देखने के लिए समय निकाला जाए।'' और फिर परिहास का पुट देते हुए शास्त्री ने कहा, ''अगर चीन की भूमि पर कुछ मशीनें या यंत्र आदि लगाए जा चुके हैं तो यह सुझाव देने के बजाय कि हमें उन्हें हटवाना चाहिए, चीन को उन्हें हटा देने में क्या बाधा है ? हमारे द्वारा उसे हटाना तभी संभव होगा जब हमारे आदमी चीन की भूमि पर जाएँ।''

२० सितम्बर को सुरक्षा परिषद में अमरीका और रूस द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जिसमें २२ सितम्बर को रात साढ़े बारह बजे से युद्धविराम की माँग की गई थी। भारत ने प्रस्ताव तुरन्त स्वीकार कर लिया लेकिन पाकिस्तान बेहतर सौदेबाजी की उम्मीद में, टाल मटोल करता रहा और अन्त में काफो देर बाद आधी रात को उसने युद्ध विराम स्वीकार किया।

सरक्षा परिषद का प्रस्ताव मोटे तौर पर भारत को मान्य शर्तो के अनुरूप ही था, यद्यपि उसमें पाकिस्तान की माँग पर वह धारा जोड़ दी गई थी जिसके अनुसार सुरक्षा परिषद का युद्धविराम और दोनों तरफ के सशस्त्र लोगों की वापसी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ''राजनैतिक मतभेदों'' पर समझौते की कोशिश करने का आदेश था। लेकिन भारत ने युद्ध विराम का संबंध किसी प्रकार के राजनीतिक समझौते के साथ जोड़ने से इन्कार कर दिया।

सुरक्षा परिषद में भारत की कूटनीति का असर पड़ा और इससे लाभ हुआ। जब पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो भारत के विरूद्ध गालियों की बौछार कर रहे थे, भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा शिष्टतापूर्वक सदन त्याग का श्रोतावर्ग पर अभीष्ट प्रभाव पड़ा। विश्व संगठन में पाकिस्तान के दोस्तों की ओर से की गई डराने धमकाने वाली तिकड़मों के मुकाबले भारत ने सफलतापूर्वक इस प्रश्न पर अंगद के पाँव जमा दिये कि कश्मीर की समस्या का सदा के लिए समाधान हो चुका है और अब पाकिस्तान द्वारा फौजी ताकत से उसे हल करने की कोशिश के बाद तो उस पर पुनर्विचार का सवाल और भी नहीं उठता। बाद, जान पड़ता है विधाता ने वह सांचा ही तोड़ दिया। अब उन जैसा कोई दूसरा नहीं है।

सन्दर्भ सूची

अग्रवाल आर.सी.	''भारतीय संविधान का विकास तथा राष्ट्रीय आन्दोलन'' एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि., रामनगर, नई दिल्ली-१९८९
अहलूवालिया, शशि	''फाउन्डर आफ न्यू इण्डिया'', एस. चन्द्र एण्ड कम्पनी लि., रामनगर, नई दिल्ली-१९९१
अंतोनोकी, को.अ., वोमदर्द-लेविन, ग्रि.क., कोतोब्स्की, ग्रि.ग्रि.	''भारत का इतिहास'', मास्को प्रगति प्रकाशन, पीपुल पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लि., नई दिल्ली-१९६६
भार्गव, जी. एस.	''आफ्टर नेहरू इण्डियाज न्यू इमेज'' एलायड पब्लिशसर्स, दिल्ली, १९६६
विपिन चन्द्र	''भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष'', हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, द्वितीय संस्करण, १९९८
विपिन चन्द्र, वरूणडे, त्रिपाठी, अमलेश	''फोडम स्ट्रगल'' नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, १९७२